भारतीय वैश्विक परिषद

सप्रू हाउस

****

फिजी गणराज्य के प्रधानमंत्री माननीय सितिवेनी लिगामामाडा राबुका द्वारा 'शांति का महासागर' विषय पर 54वें सप्रू हाउस व्याख्यान की प्रतिलिपि, 26 अगस्त 2025

प्रज्ञा पांडे: देवियो और सज्जनो, फिजी गणराज्य के माननीय प्रधानमंत्री सप्रू हाउस परिसर में आ चुके हैं और वे शीघ्र ही यहां आएंगे। कृपया बैठ जाइए। देवियो और सज्जनो, फिजी गणराज्य के प्रधानमंत्री माननीय सितिवेनी लिगामामाडा राबुका आ चुके हैं। कृपया खड़े होकर तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। धन्यवाद। मंच पर उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों, सम्मानित श्रोतागण, राजनयिक दल के सदस्यों, सम्मानित शिक्षाविदों, मीडिया के प्रतिनिधियों और छात्रों को शुभ संध्या। हम आज यहां 54वें सप्रू हाउस व्याख्यान के लिए एकत्रित हुए हैं। आज का व्याख्यान फिजी गणराज्य के प्रधानमंत्री, विदेश, सिविल सेवा एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्री, महामहिम सितिवेनी लिगामामाडा राबुका द्वारा "शांति का महासागर" विषय पर दिया जाएगा। व्याख्यान की अध्यक्षता भारतीय वैश्विक परिषद की कार्यवाहक महानिदेशक और अपर सचिव सुश्री नूतन कपूर महावर करेंगी। हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत आईसीडब्ल्यूए की कार्यवाहक महानिदेशक, सुश्री नूतन कपूर महावर के स्वागत भाषण से करेंगे, जिसके पश्चात् हमारे सम्मानित अतिथि 54वां सप्रू हाउस व्याख्यान देंगे। व्याख्यान के बाद थोड़े समय के लिए प्रश्नोत्तर सत्र होगा, जिसका संचालन अध्यक्ष करेंगे। अब मैं कार्यवाहक महानिदेशक, सुश्री नूतन कपूर महावर को उनके स्वागत भाषण और कार्यवाही का संचालन करने हेतु आमंत्रित करती हूँ।

नूतन कपूर महावर : महानुभाव, राजनयिक दल, शिक्षा जगत, मीडिया के विशिष्ट सदस्यगण और छात्रगण। आज के शांति के महासागर विषय पर आयोजित 54वें सप्रू हाउस व्याख्यान में फिजी गणराज्य के प्रधानमंत्री माननीय सितिवेनी लिगामामाडा राबुका की मेज़बानी करना हमारे लिए गर्व की बात है। भारत के सबसे पुराने और अग्रणी विदेश नीति थिंक टैंक, भारतीय वैश्विक परिषद की इस सप्रू हाउस व्याख्यान श्रृंखला में पहले भी कई प्रतिष्ठित हस्तियां आ चुकी हैं, जिनमें कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष एवं सरकार के प्रमुख, अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के प्रमुख और अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल हैं। माननीय प्रधानमंत्री राबुका का राजनीतिक जीवन काफी लंबा और प्रतिष्ठित रहा है। प्रधानमंत्री के रूप में, उन्होंने फिजी और उसके लोगों की भलाई तथा विकास हेतु निरंतर प्रयास किए हैं। उनके नेतृत्व में, फिजी छोटे द्वीपीय देशों के लिए क्लाइमेट जस्टिस

के मुखर समर्थक के रूप में उभरा है। वे प्रशांत क्षेत्र में मजबूत क्षेत्रीय एकता और संवाद के पक्षधर रहे हैं। खुद एक एथलीट और प्रतिष्ठित खिलाड़ी होने के नाते, वह खेलों जैसे क्षेत्रों में लोगों के बीच अच्छे जुड़ाव के ज़रिए प्रशांत क्षेत्र में बढ़ते संबंधों के महत्व का प्रतीक हैं।

भारत और फिजी गणराज्य के बीच अच्छे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। भौगोलिक दूरी के बावजूद, हमारे इतिहास समय के साथ प्रवास के धागों से गुंथे हुए हैं। औपनिवेशिक काल के दौरान, भौगोलिक रूप से दूर होने के बावजूद, फिजी में रहने वाले भारतीय-फिजीवासियों ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम से प्रेरणा ली, जिसके परिणामस्वरूप सभी फिजीवासियों में औपनिवेशिक शोषण का विरोध करने हेतु व्यापक राजनीतिक चेतना और संगठन की भावना आई, जिससे औपनिवेशिक उत्पीड़न के विरुद्ध खड़े होने का साझा इतिहास बना। भारतीय मूल के कई श्रमिक उस समय फिजी चले गए जब भारत और फिजी दोनों ब्रिटिश उपनिवेश थे। ये श्रमिक यहीं रहे, कभी वापस नहीं लौटे, फिजी को अपना घर बना लिया और इसकी अर्थव्यवस्था, समाज तथा धीरे-धीरे इसकी राजनीति में अपना योगदान दिया। हम भारतवासियों को तब अधिक प्रसन्नता होती है जब फिजी के नेता हमें भारतीय मूल के लोगों के अपने समाज में पूर्ण एकीकरण का आश्वासन देते हैं और हमें राष्ट्र की समृद्धि, कल्याण और सांस्कृतिक परिवेश में उनके जीवंत योगदान की कहानियाँ बताते हैं।

आज, भारत और फिजी के बीच मज़बूत द्विपक्षीय संबंध हैं। विगत कुछ वर्षों में भारत की ओर से फिजी की लगातार उच्च-स्तरीय यात्राओं से इन संबंधों की प्रगाढ़ता दिखती है, जिसमें 2024 में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की हालिया यात्रा भी शामिल है। प्रशांत महासागर में एक महत्वपूर्ण महासागरीय देश होने के नाते, फिजी की पहचान, विकास एवं चुनौतियाँ महासागर से जुड़ी हैं। दोनों समुद्री राष्ट्र होने के नाते, समुद्री सहयोग एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसे भारत और फिजी के बीच सहयोग के प्रमुख क्षेत्र के रूप में आगे बढ़ाने की ज़रुरत है। भारतीय नौसेना के जहाजों ने अपनी परिचालन तैनाती के हिस्से के रूप में फिजी की सद्भावना यात्राएँ की हैं। कई कार्यों में इस्तेमाल होने वाले युद्धपोत आईएनएस सतपुड़ा की 2022 में सुवा यात्रा इसमें सबसे अहम है। भारत ने चक्रवात के दौरान फिजी को मानवीय सहायता और आपदा राहत प्रदान की है। जब 2020 में चक्रवात यासा से फिजी प्रभावित हुआ, तो भारत ने खुद महामारी से निपटते रहने के बावजूद समय पर सहायता प्रदान की। और इतना ही नहीं, भारत ने कोविड के दौरान फिजी को ज़रुरी टीके और आवश्यक दवाइयाँ प्रदान कीं, जो हमारे गहरे और मैत्रीपूर्ण संबंधों का प्रतीक है।

मित्रों, वैश्विक व्यवस्था में बदलाव हो रहा है, और हमें दुनिया के हर हिस्से में रणनीतिक अनिश्चितता देखने को मिल रही है। महाशक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा, आर्थिक असमानताएँ, तकनीकी व्यवधान एवं पर्यावरणीय दबाव सुरक्षा को अलग तरीके से परिभाषित कर रहे हैं। प्रशांत

द्वीपीय देश भी विशाल हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बढ़ती भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के प्रभाव को महसूस कर रहे हैं। दुनिया और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में इस भू-राजनीतिक उथल-पुथल के बीच, भारत एक नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर आधारित एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी, शांतिपूर्ण एवं समृद्ध हिंद-प्रशांत क्षेत्र के अपने दृष्टिकोण और इस दृष्टिकोण के आधार पर साझेदारी बनाने हेतु प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री राबुका की शांति के महासागर की अवधारणा, जिस पर वे आज बोलेंगे, क्षेत्रवाद की दिशा में अगला कदम है, जिसमें ऐसे सिद्धांत हैं जो शांति को प्रशांत क्षेत्र की व्यक्तिगत एवं सामूहिक नीतियों की आधारशिला के रूप में स्थापित करते हैं। रणनीतिक रूप से विशाल और संसाधन-समृद्ध विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों वाला होने के बावजूद, प्रशांत द्वीपीय देश जलवायु परिवर्तन और समुद्र के स्तर में वृद्धि की कमज़ोरियों के प्रति अलग-अलग कारणों से संवेदनशील हैं, और ऐसी चुनौतियों से निपटने की उनकी क्षमता काफी सीमित है। वर्तमान भू-राजनीतिक स्थिति के बीच, प्रशांत द्वीप क्षेत्र में फिजी की नेतृत्वकारी भूमिका जलवायु परिवर्तन, अवैध मछली पकड़ने आदि जैसी छोटे द्वीप देशों की साझा चुनौतियों से निपटने हेतु सामूहिक कार्रवाई की ज़रुरत की वकालत करने और आह्वान करने में महत्वपूर्ण बनी हुई है।

प्रशांत द्वीप देशों के प्रति भारत का दृष्टिकोण और पहुंच लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार और सशक्तिकरण में योगदान करने के समग्र उद्देश्य पर आधारित है। भारत-प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच, एफआईपीआईसी, जिसे 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक यात्रा के दौरान फिजी में लॉन्च किया गया था, ने भारत और पीआईसी को और भी करीब ला दिया है, और बहुआयामी सहयोग पर चर्चा करने हेतु एक मंच प्रदान किया है। भारत प्रमुख क्षेत्रों में पीआईसी हेतु एक विकास भागीदार है, जिसमें स्वास्थ्य सेवा, आपदा प्रबंधन, जलवायु लचीलापन का सृजन, सौर, नवीकरणीय ऊर्जा और जलवायु संबंधी परियोजनाएं, एसएमई, सूचना प्रौद्योगिकी, कृषि और भारत के आईटीईसी कार्यक्रम के तहत क्षमता सृजन का क्षेत्र शामिल है। भारत की आउटरीच छोटे द्वीप देशों की प्राथमिकताओं द्वारा निर्देशित समावेशी संबंधों पर केंद्रित है। प्रशांत क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा समर्थित अब तक की सबसे बड़ी विकास परियोजना फिजी में है, जहाँ सुवा में 100 बेड वाला एक सुपरस्पेशलिटी अस्पताल बनाया जा रहा है, जो किफायती स्वास्थ्य सेवा की एक बहुप्रतीक्षित परियोजना है जिसकी घोषणा 2023 में तीसरे एफआईपीआईसी शिखर सम्मेलन में की गई थी। फिजी में जन औषधि केंद्रों या पीपुल फार्मेसीज़ की शुरुआत पर भी दोनों पक्षों ने सहमति जताई है।

जैसा कि मैंने कहा, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास, पीआईसी में चिंता के महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। इन्हीं क्षेत्रों में भारत प्रभावी और ठोस समाधानों हेतु घनिष्ठ साझेदारी चाहता है। फिजी पहले से ही भारत की वैश्विक पहलों का हिस्सा है, जो जलवायु परिवर्तन एजेंडे के प्रति हमारी क्षेत्रीय एवं वैश्विक प्रतिबद्धता का अभिन्न हिस्सा हैं, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, आपदा रोधी

अवसंरचना गठबंधन, सीडीआरआई, और लचीले द्वीपीय राष्ट्रों के लिए अवसंरचना, आईआरआईएस, और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन शामिल हैं। मित्रों, वैश्विक दक्षिण के पुनरुत्थान से वैश्विक गतिशीलता को नया आकार मिल रहा है। आज वैश्विक दक्षिण वैश्विक विषमताओं के विरुद्ध एकजुट होकर आवाज उठाने और एक बहुध्रुवीय विश्व तथा सुधरी हुई बहुपक्षीय व्यवस्था को आकार देने में योगदान देने का प्रयास कर रहा है। छोटे संवेदनशील महासागरीय देशों की आवाज को उठाने और जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक संवाद तथा जलवायु न्याय की वकालत करने में फिजी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। फिजी 2017 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन सीओपी 23 की अध्यक्षता करने वाला पहला छोटा द्वीप था। वैश्विक दक्षिण की अग्रणी आवाज के रूप में, भारत, को-ऑपरेटिव सुरक्षा एवं सामूहिक विकास का आह्वान करते हुए, जलवायु न्याय और चिंता के अन्य मुद्दों पर फिजी और अन्य छोटे महासागर राष्ट्रों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा।

चूंकि भारत और फिजी 2025 में अपने औपचारिक राजनयिक संबंधों की 55वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, इसलिए हम अपने साझा मूल्यों और ऐतिहासिक सांस्कृतिक संबंधों को दोहराते हैं तथा मौजूदा तथा उभरते क्षेत्रों में सहयोग और साझेदारी बढ़ाने की उम्मीद करते हैं। इसी के साथ, मैं फिजी के माननीय प्रधानमंत्री, सितिवेनी राबुका को "शांति का महासागर" विषय पर 54वें सप्रू हाउस व्याख्यान देने हेतु आमंत्रित करती हूँ। महोदय।

सितिवेनी लिगामामाडा राबुका: राजदूत महावर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। देवियो और सज्जनो, मैं यह देख रहा हूँ कि श्रोताओं में कुछ युवा भी हैं, जो भविष्य के नेता हैं। मैं सभी को राष्ट्रपति, सरकार, प्रमुखों और फिजी की जनता की ओर से शुभ संध्या कहता हूँ और हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ। शांति के महासागर की अवधारणा पर कुछ टिप्पणियाँ करने हेतु नई दिल्ली आना मेरे लिए विशेष सम्मान की बात है, जिसका मैं इस दशक में संभवतः प्रमुख समर्थक रहा हूँ। ऐसे कई लोग रहे हैं जिन्होंने प्रशांत महासागर को शांति के महासागर के रूप में दर्शाने का प्रयास किया है। हमारे नीले प्रशांत महाद्वीप के विशाल और परस्पर जुड़े विस्तार और हमारे अपने क्षेत्र व उससे आगे के क्षेत्रों पर इसके बहुआयामी प्रभाव को ध्यान में रखते हुए मैंने ऐसा इसलिए किया या मेरा ऐसा विचार बना। हमारा द्वीपीय राष्ट्र प्रशांत महासागर में छोटा और बिखरा हुआ हो सकता है। लेकिन, साथ मिलकर, हमारा नीले प्रशांत महासागर के 32 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर संप्रभु अधिकार हैं। यह क्षेत्र अकेले रूस, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के संयुक्त भू-भाग से थोड़ा ही छोटा है। फिर भी, प्रशांत क्षेत्र के लोग लचीले बने हुए हैं। हमारी पहचान साझा है और अपने महासागर के प्रति सुरक्षा से एकजुट हैं, हालाँकि प्रशांत महासागर पूरे विश्व का महासागर है। इसी लचीलेपन और एकता ने शांति के महासागर की अवधारणा और भविष्य के लिए इसके दृष्टिकोण को प्रेरित किया है। नीले प्रशांत महासागर के सामूहिक क्षेत्र को देखते हुए,

यह एक विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र है और भू-रणनीतिक महत्व के नज़रिए महत्वपूर्ण है। यह हमारे क्षेत्र और विश्व हेतु काफी भू-रणनीतिक महत्व रखता है। मैं अपने क्षेत्र और उससे आगे की भविष्य की सुरक्षा और समृद्धि हेतु शांति के महासागर की अवधारणा का पूरे जोश के साथ समर्थन करता रहूँगा।

इस भविष्य के दृष्टिकोण पर विचार करते समय, हमें अपने अत्यंत समृद्ध इतिहास और अपनी अनूठी विरासत को भी ध्यान में रखना चाहिए। हमारे पूर्वजों ने लगभग 3,000 वर्ष पूर्व विशाल आउट्रिगर डोंगियों में अज्ञात जगहों की यात्रा की थी। वे उस समय केवल तारों को देखते हुए, अद्भुत नौवहन क्षमता के सहारे दिशाओं यात्रा करते थे। वो महीने-दर-महीने अनगिनत मील की यात्रा करते रहे और अंततः उन द्वीपों और प्रवालद्वीपों पर बस गए जिन्हें उन्होंने खोजा था। यह मानव जाति के सबसे महत्वपूर्ण प्रवासों में से एक है, जो मानवीय सहनशक्ति, साहस व उपलब्धि का प्रमाण है। हम ऐसे लोग हैं जो समुद्र व भूमि के साथ एकाकार हैं, और ऐसी सभ्यता बना रहे हैं जो आज भी फल-फूल रही है। ऐसे में इतिहास के अत्यंत महत्वपूर्ण व प्रसिद्ध पुर्तगाली नाविक, फर्डिनेंड मैगलन, जिन्होंने 1522 में प्रशांत महासागर को पार किया था, का उल्लेख न करना एक बड़ी भूल होगी। यह नीले प्रशांत महासागर की शुरुआती यूरोपीय खोज का युग था। मैगलन का जिक्र इसलिए किया जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने हमारे जलीय महाद्वीप, जो आज भी विद्यमान है, को प्रशांत नाम दिया, जिसका अर्थ है शांतिपूर्ण। मैगलन ने जिस जल क्षेत्र को पार किया वह उस समय शांत था। हालाँकि, हम सभी जानते हैं कि प्रशांत महासागर का जल हमेशा से ऐसा नहीं रहा है। नीला प्रशांत क्षेत्र बाहरी युद्धों का अखाड़ा रहा है। इसे सबसे खतरनाक हथियारों का परीक्षण स्थल माना गया है। इसने जलवायु परिवर्तन और कई लोगों द्वारा दोहन किए गए इसके समृद्ध संसाधनों के कारण होने वाली भयावह आपदाओं को सहन किया है। यह नीले प्रशांत क्षेत्र की मौजूदा वास्तविकता है। सुरक्षा गतिशीलता को समझते हुए, सितंबर 2024 में, फिजी ने अपनी पहली विदेश नीति श्वेत पत्र जारी किया, जो स्पष्ट करता है कि हमारे लिए सुरक्षा का सबसे बड़ा खतरा ऐसे व्यापक क्षेत्र की संभावना में निहित है जो विभाजन, असुरक्षा और अस्थिरता से प्रेरित है। उन गतिशीलता को ध्यान में रखते हुए, फिजी व्यापक हिंद-प्रशांत क्षेत्र में एक रणनीतिक संतुलन स्थापित करने में सबसे बड़ा योगदान कर सकता है। इसके लिए हमारे अपने प्रशांत पड़ोस में शांति और सुरक्षा की चुनौती पर ध्यान केंद्रित करना होगा।

जब मैं फ़िजी सेना का कमांडर था, तब शांति सैनिकों की भर्ती के विदाई समारोह में मैंने उनसे कहा था कि हम किसी को भी वह चीज़ नहीं दे सकते जो हमारे पास नहीं है। और हम 1978 से मध्य पूर्व में शांति की स्थापना कर रहे हैं। और लोग पूछते हैं, आप कहाँ से हैं? फ़िजी से। वह कहाँ है? प्रशांत महासागर में। इसलिए मैंने सोचा कि इन शांति सैनिकों के पूरे होमलैंड में, उनके खुद के क्षेत्र में, हमें जो सबसे पहली चीज़ करनी चाहिए, वह है उस शांति को दूसरे देशों तक ले

जाना जो हम पहले से ही अपने देश में महसूस करते हैं। इसीलिए मैंने प्रशांत क्षेत्र को शांति का क्षेत्र या महासागर बनाने की वकालत की है। विगत कुछ वर्षों से शांति की यह चुनौती मेरे सामने सीधे तौर पर आ रही है, और वास्तव में, जब से मैं शांति का रक्षक और एक राजनेता बना हूँ, मैं अपने देश में शांति खत्म होने और अब देश व व्यापक प्रशांत क्षेत्र में शांति की बहाली हेतु बाकी दुनिया के सामने वकालत करने की अपनी ज़िम्मेदारी महसूस करता हूँ। इस वजह से, मैं उस भू-रणनीतिक प्रतिस्पर्धा को लेकर बहुत चिंतित हूँ जो इस समय नीले प्रशांत क्षेत्र के सामने है, और दुनिया भर में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों ने इसे और बढ़ा दिया है। हम ऐसे दौर में हैं जहाँ दुनिया भर में आर्थिक अनिश्चितता बढ़ रही है, और यह हमारे भौगोलिक रूप से फैले प्रशांत क्षेत्र के देशों में बहुत अधिक महसूस किया जा रहा है। वैश्विक नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था अपनी सीमाओं तक परखी जा चुकी है, और लंबे समय से चल रहे संघर्षों और मानवीय आपदाओं के कारण बहुपक्षवाद खत्म हो रहा है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से उत्पन्न अस्तित्वगत खतरे ने स्थिति को और भी मुश्किल बना दिया है। समुद्र का बढ़ता स्तर, लगातार गंभीर होती मौसम की स्थितियाँ, मौसमी घटनाएँ और बदलता पारिस्थितिकी तंत्र। ये हमारे जीवन के तौर-तरीकों और नीले प्रशांत क्षेत्र में हमारे अस्तित्व हेतु खतरा हैं। और इससे मुझे यह सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि हम प्रशांत में स्थित के परिवार के तौरपर, शांति के महासागर की अवधारणा के ज़रिए ऐसा क्या कर सकते हैं, जो संवाद, कूटनीति और आम सहमति के प्रशांत तरीके पर आधारित हो। मैंने हमेशा सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि हेतु प्रशांत दृष्टिकोण में विश्वास किया है। जब हम एक साथ खड़े होते हैं तो हम और भी मज़बूत होते हैं।

2023 में रारोटोंगा में प्रशांत द्वीप मंच की बैठक में, मैंने प्रस्ताव रखा था कि क्षेत्रीय नेता ऐसे सिद्धांतों पर सहमत हों जो शांति को क्षेत्र में हमारी व्यक्तिगत एवं सामूहिक नीतियों का आधार हो। मैं शांति के महासागर की अवधारणा पर थोड़ा विस्तार से चर्चा करना चाहूँगा। इस अवधारणा का मूल ऐसी साझा आकांक्षा है, जो हमारी परंपराओं में निहित है और क्षेत्रीय सहयोग, स्थिरता और स्थिरता हेतु सहयोग की सामूहिक प्रतिबद्धता द्वारा निर्देशित है। यह हमारे लोगों को स्वतंत्र, स्वस्थ एवं अच्छा जीवन जीने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। शांति के महासागर की अवधारणा इस बात का संकेत है कि हम ऐसा क्षेत्र बनाना चाह रहे हैं जहाँ रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का प्रबंधन हो, जहाँ स्थिरता क्षेत्रीय संबंधों की कसौटी हो, और जहाँ दबाव पर नियंत्रण रखा जाए। यह अवधारणा मेरे इस विश्वास को दर्शाती है कि एकजुट क्षेत्र ही मजबूत क्षेत्र होता है, और जब हम एक स्वर में बोलते हैं, तो हमारी शक्ति बढ़ जाती है। यह अवधारणा हमें शांतिपूर्ण विकास हेतु प्रतिबद्ध रहने का भी आह्वान करती है, क्योंकि हमारे देशों में स्थायी शांति हेतु राष्ट्रीय सुरक्षा और सतत विकास के बीच संतुलन की ज़रुरत होती है। ऐसी शांति केवल हमारी पुलिस या सुरक्षा बलों के ज़रिए नहीं बनाई जा सकती। इसके लिए ऐसे परिवारों, समुदायों, समाजों और राष्ट्रों

की भी ज़रुरत होती है जो सद्भाव, स्थिरता, जीवन से संतुष्टि और अभाव व भय से मुक्ति की नींव पर निर्मित हों। शांति का महासागर उस अवधारणा के मूल सिद्धांतों पर आधारित है जो मुख्यतः प्रशांत क्षेत्रवाद के हमारे मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित है। यह हमारे लिए अपने प्रशांत अतीत के धागों को अपने प्रशांत भविष्य हेतु एक दृष्टिकोण के साथ बुनने का अवसर है। शांति के महासागर की अवधारणा निम्नलिखित बारह सिद्धांतों पर आधारित है। प्रशांत तरीकों पर आधारित विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की साझा प्रतिबद्धता। अंतर्राष्ट्रीय कानून एवं मानदंडों का सम्मान। हम 12 नवंबर, 1984 को अपनाए गए लोगों के शांति के अधिकारों पर महासभा की घोषणा का स्मरण करते हैं। सुरक्षा, आर्थिक या राजनीतिक लाभ हासिल करने के साधन के रूप में किसी भी तरह के दबाव को अस्वीकार करना। अपनी सुरक्षा और रणनीतिक नीतियों को निर्धारित करने की आजादी। नौवहन और उसके ऊपर से उड़ानों की आजादी को कायम रखना। जिम्मेदार, शांतिपूर्ण, संघर्ष-मुक्त व्यवहार के नियमों को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न हितधारकों से आह्वान, और 12वां सिंधांत, हमारे लोगों को एक साथ लाना। ये सिद्धांत प्रशांत क्षेत्र के तरीके पर आधारित हैं। ये हमें यह तय करने का अवसर भी देते हैं कि हम क्षेत्र के बाहर के लोगों से क्या अपेक्षा करते हैं कि वे हमारे दृष्टिकोणों का सम्मान करें और हमारे साथ भागीदारी करें। यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब यह है कि प्रशांत क्षेत्र के तरीके का सम्मान, बिना किसी दबाव के मानदंडों और कानून का सम्मान। इन सिद्धांतों के आधार पर, यह अवधारणा हमारी एकता को मजबूत करने और हमारे द्वीपों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभारने का काम करेगी, जिससे पर्यटन, निवेश और विकास के अवसर बढ़ेंगे। इन सिद्धांतों को कायम रखकर, हम प्रशांत क्षेत्र की एकता को मजबूत कर सकते हैं, अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि को बढ़ा सकते हैं, और पर्यटन, व्यापार, निवेश व विकास के नए अवसर पैदा कर सकते हैं।

इस दिशा में, भारत एक अहम भागीदार है। द्विपक्षीय रूप से, डिजिटल सॉल्यूशन, स्वास्थ्य सेवा, नवीकरणीय ऊर्जा, शिक्षा व कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में भारत का समर्थन फिजी को अपने लोगों को लचीलापन और समृद्धि बनाने में मदद करता है। बहुपक्षीय रूप से, भारत संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर फिजी की आवाज़ को उठा सकता है, निर्णायक जलवायु कार्रवाई, परमाणु अप्रसार एवं संयुक्त राष्ट्र चार्टर तथा संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन (यूएनसीएलओएस) के तहत नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के हमारे आह्वान का समर्थन कर सकता है। फिजी और भारत मिलकर यह सुनिश्चित करने का काम कर सकते हैं कि प्रशांत महासागर को शांति के महासागर के रूप में देखना न केवल हमारे क्षेत्र के लिए, बल्कि दुनिया की शांति और स्थिरता के लिए भी एक वास्तविकता बने।

अंत में, महामहिम, देवियो और सज्जनो, मेरा मानना है कि शांति के महासागर की अवधारणा के ज़रिए दुनिया के साथ प्रशांत महासागर के तरीके को साझा करने के अवसर उपलब्ध हैं। शांति के

महासागर की अवधारणा का कार्यान्वयन प्रशांत, हिंद-प्रशांत और उससे आगे के सभी लोगों की भागीदारी वाला एक साझा प्रयास है। हमें इस पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने नीले प्रशांत क्षेत्र, अपने शांति महासागर की रक्षा हेतु मिलकर काम करना चाहिए। पिछले सप्ताह, शांति के महासागर घोषणापत्र का मसौदा हमारे प्रशांत द्वीप मंच के नेताओं की अभिन्न प्रक्रियाओं, वरिष्ठ अधिकारियों की बैठकों और मंच के विदेश मंत्रियों की बैठकों के ज़रिए पारित किया गया था। अब यह मसौदा घोषणापत्र प्रशांत द्वीप मंच के नेताओं के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जिन पर अगले महीने सोलोमन द्वीप समूह के होनियारा में होने वाली उनकी बैठक में विचार किया जाएगा। मैं शांति के महासागर की अवधारणा को साकार करने और इसके ज़रिए विश्व शांति, विश्व सुरक्षा और मानव जाति की गरिमा हेतु हम जो कुछ भी कर सकते हैं, उसमें भारत गणराज्य की सरकार के सहयोग की उम्मीद करता हूँ। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।

नूतन कपूर महावर : महामहिम, 54वें सप्रू हाउस व्याख्यान देने और शांति के महासागर की अपनी अवधारणा पर हमारे साथ अपने विचार साझा करने हेतु आपका धन्यवाद। प्रशांत क्षेत्र के लिए इस अवधारणा और दृष्टिकोण का आपका कुशल नेतृत्व, फिजी की नेतृत्वकारी भूमिका और अपने क्षेत्र में स्थिर आवाज़ को दर्शाता है। शांति के महासागर की अवधारणा, जैसा कि आपने कहा, इस क्षेत्र में वर्तमान में देखी जा रही भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का एक जवाब है, जिसे स्वायत्तता की रक्षा और सशक्तीकरण हेतु साथ मिलकर प्रबंधित करने की ज़रुरत है। यह अवधारणा जैसा कि आपने कहा, प्रशांत संवाद और आम सहमति पर आधारित है। जब क्षेत्रीय और वैश्विक शांति व सुरक्षा में योगदान की बात आती है, तो किसी भी क्षेत्र की आवाज़ सुनी जानी चाहिए। मुझे विश्वास है कि आज हमारे श्रोताओं ने आपके व्याख्यान को बेहद रुचि के साथ सुना होगा। मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री ने व्याख्यान के विषय, यानी शांति के महासागर के बारे में माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण, जिसके बारे में आपने अभी सुना है, पर श्रोताओं के कुछ सवालों के उत्तर देंगे, और इसके लिए हम उनके आभारी हैं। प्रधानमंत्री जी, अगर आपकी अनुमति हो, तो क्या हम कुछ सवाल ले सकते हैं? धन्यवाद। तो अब आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, कृपया केवल आज के व्याख्यान के विषय, यानी प्रधानमंत्री की शांति के महासागर की अवधारणा और इसके दृष्टिकोण पर ही प्रश्न पूछे। मैं प्रतिभागियों से अनुरोध करती हूँ कि प्रश्न पूछने से पहले अपना परिचय दें और कृपया अपना प्रश्न छोटा रखें। तो अब आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ। पहले आप।

अवनी सबलोक: इस ज्ञानपूर्ण व्याख्यान हेतु धन्यवाद, और मेरा नाम अवनी सबलोक है, और मेरा प्रश्न यह है कि आपकी शांति का महासागर संबंधी विज़न क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समर्थन पर निर्भर करता है। क्या आप इसे संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन जैसे अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाने का प्रस्ताव रखते हैं, और क्या आप वैश्विक दक्षिण का समर्थन भी चाहते हैं? धन्यवाद।

सितिवेनी लिगामामाडा राबुका: धन्यवाद महोदया। मैंने इसे पहली बार 2023 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार उपस्थित होने के दौरान पेश किया था। सितंबर 2023 में, मैंने संयुक्त राष्ट्र महासभा से वादा किया था कि मैं इसे वापस उठाऊँगा, लेकिन प्रशांत द्वीप समूह के नेताओं के मंच के ज़रिए, जो मैंने किया है, और मैंने अपने संबोधन में इसका उल्लेख किया था। हमने प्रशांत क्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इसके विभिन्न पहलुओं और घोषणापत्र की संरचना पर विचार-विमर्श किया है। प्रशांत द्वीप समूह के विदेश मंत्रियों ने भी इस पर विचार किया है। महोदया, आपने जिन विश्व संस्थानों का उल्लेख किया है, उनके साथ मेरी द्विपक्षीय बैठकें भी हुई हैं। मैं इस साल की शुरुआत में म्यूनिख सिक्योरिटीज़ कॉन्फ्रेंस में था, और मैंने एक पैनल चर्चा की, और मैंने उन्हें प्रशांत क्षेत्र के बारे में बताया। यह प्रशांत क्षेत्र में कोई अनोखा विषय नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ है जिसके बारे में हमने शायद ज़्यादा नहीं सोचा है। यह हमारे घरों में रोज़ होता है। जब कोई परिवार इकट्ठा होता है, तो आमतौर पर हम खाना नहीं खाते अगर परिवार का सबसे छोटा सदस्य रो रहा हो या परेशान हो। इसलिए माता-पिता शायद इंतज़ार करेंगे, और बड़े भाई-बहन बच्चे को शांत करने की कोशिश करेंगे जब तक कि हम सब शांत न हो जाएँ। और यही वह अवधारणा है जिसे मैं दुनिया के सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब प्रशांत महासागर के छोटे द्वीपीय देश दुनिया में हो रही घटनाओं से परेशान होते हैं, तो हम दुनिया से हमारी बात सुनने का अनुरोध करते हैं। हम इस अवधारणा को बढ़ावा देने हेतु अपने स्वयं के महासागर, शांति के महासागर की घोषणा करना चाहते हैं, जहाँ हम प्रशांत क्षेत्र में एक-दूसरे के साथ शांति से रहें, जहाँ हम अनुरोध करें कि बड़ी शक्तियों के संघर्ष प्रशांत क्षेत्र तक न आएँ। आपने मुझे कई बार "बलपूर्वक" शब्द का ज़िक्र करते सुना होगा, जहाँ वे आकर हमारे कुछ नेताओं के वोट को अपने पक्ष में प्रभावित करने की कोशिश कर सकते हैं। मेरी राय में, मैंने उनके साथ अपनी चर्चाओं में ये मुद्दे उठाए हैं। मैंने राष्ट्रमंडल नेताओं के साथ भी कई बार इस मुद्दे को उठाया है। इसलिए जब मैंने 2023 में इसका ज़िक्र किया, तो मैं वापस आया और उन नेताओं के सामने इस अवधारणा को बढ़ावा देने हेतु खुद काम किया, जिनके साथ इस दौरान मुझे जुड़ने का मौका मिला। अब मैं कुछ दिनों में होनियारा में पीआईएफ नेताओं की बैठक के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा में वापस जा रहा हूँ, और उम्मीद है कि मैं वह घोषणापत्र पेश करूँगा जिस पर प्रशांत क्षेत्र के सभी नेता प्रतिबद्ध हैं। और चूँकि हम शायद दुनिया के सबसे छोटे द्वीपीय देशों के समूह से हैं, इसलिए हमें उम्मीद है कि प्रशांत क्षेत्र और दुनिया में एक परिवार की अवधारणा को हमारे नेता विदेशों तक ले जाएँगे। और जब सबसे बड़े महासागर में सबसे छोटे देशों के सबसे छोटे लोग कहेंगे, "हमारी मदद करो," तो हर कोई बैठकर हमारी बात सुनेगा।

नूतन कपूर महावर : धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। अगला सवाल, हाँ। नीली शर्ट पहने हुए लड़का।

केशव वर्मा: महामहिम, आपके गहन व्याख्यान हेतु धन्यवाद। मैं केशव हूँ। तो मेरा प्रश्न यह है कि आपके द्विपक्षीय संवादों में शांति के महासागर की आपकी अवधारणा को अन्य देश कैसे स्वीकार कर रहे हैं? क्या उन्होंने प्रशांत द्वीप समूहों में इस पहल को बढ़ावा देने पर कोई प्रतिबद्धता व्यक्त की है? धन्यवाद।

सितिवेनी लिगामामाडा राबुका: मेरी संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ कोई व्यक्तिगत बातचीत नहीं हुई है। मैंने रूस के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक का अनुरोध किया है। मैंने पहले और अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठकें की हैं। इस क्षेत्र के सभी प्रधानमंत्री इस अवधारणा पर एकमत हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल हमारी बातचीत में हमारी भावनाओं तथा अवधारणा को दोहराया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस साल की शुरुआत में और पिछले साल भी हमारी चर्चा में इस मुद्दे को उठाया था। बहुत से लोगों, बड़े देशों के बड़े नेताओं ने इसे सुना है। और र मैंने परिवार की इस अवधारणा को सामने रखा और परिवार के सबसे छोटे या सबसे छोटे सदस्य के असहज होने की स्थिति में हर कोई ध्यान से सुनता है। क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है, उसका असर हम पर पड़ रहा है। अब जो कुछ भी हो रहा है, उसका असर संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ आपके संबंधों पर पड़ रहा है। टैरिफ की हालिया घोषणा और कुछ चीजें जो प्रधानमंत्री मोदी की ओर आ रही हैं। मैंने उनसे एक दिन कहा था, कोई आपसे बहुत खुश नहीं है, लेकिन फिर भी आप उन परेशानियों को झेलने में काफी समर्थ हैं। हाँ, लोग हमारी बात सुन रहे हैं। हमारा काम दुनिया को यह बताना है कि हमने प्रशांत महासागर में शांति के महासागर के लिए इस अवधारणा की घोषणा की है। संयुक्त राष्ट्र को इसे अपनाना और आगे बढ़ाना है, और क्षेत्रीय नेताओं को इसे अपनाना है और अपनी क्षेत्रीय अवधारणा और क्षेत्रीय नेताओं की बैठकों में इसे उठाना है। और उम्मीद है कि हम शांति ला पाएँगे। जब मैं संयुक्त राष्ट्र में शांतिदूत था, तो मैं सोचता था कि जब शांति बनाए रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, तो संयुक्त राष्ट्र हमें शांतिदूत क्यों कहता है? हम शांति लागू भी नहीं कर सकते थे, लेकिन हमें शांतिदूत कहा जाता था। मैंने चार साल उस शांति को बनाए रखने की कोशिश में बिताए जो मध्य पूर्व में अस्तित्वहीन थी। हमें अभी स्थिरता दिखना शुरू ही हुई थी, और फिर यह फिर से भड़क उठी। इसलिए उम्मीद है कि ज़्यादा लोग आगे आएंगे, सुनेंगे और अपनाएंगे, कि आप बातचीत, क्षेत्रीय सहमति और शांति हेतु सामूहिक सहयोग के ज़रिए मतभेदों को सुलझा सकते हैं।

नूतन कपूर महावर : धन्यवाद। अगला प्रश्न। तो हाँ, यहाँ मौजूद महिला, हाँ, कृपया आप।

नंदिनी खंडेलवाल: शांति के सागर विषय पर इतना महत्वपूर्ण व्याख्यान देने हेतु आपका धन्यवाद। मैं परिषद में शोध विश्लेषक नंदिनी खंडेलवाल हूँ। आपका दृष्टिकोण दक्षिण प्रशांत क्षेत्र को स्थिरता, एकता व शांति, लचीलेपन के प्रति प्रतिबद्धता और, जैसा कि आपने कहा, राष्ट्रीय सुरक्षा और

सतत विकास के बीच संतुलन के क्षेत्र के रूप में स्थापित करना है, जो क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने की दिशा में एक कदम है। अब आपने इसे हासिल करने हेतु कुछ सिद्धांतों का भी उल्लेख किया है। तो क्या कोई विशिष्ट तंत्र हैं जिसका आप प्रशांत क्षेत्र के छोटे द्वीपीय देशों के बीच साझा चुनौतियों का समाधान करने हेतु इस एकता और सामूहिक कार्रवाई को बढ़ावा देने हेतु प्रस्ताव कर सकते हैं? धन्यवाद।

सितिवेनी लिगामामाडा राबुका: धन्यवाद। प्रशांत क्षेत्र में हमारे लिए, विगत दो वर्षों में मैंने जिस एकमात्र सहयोग की अपेक्षा की है, वह है घोषणापत्र पर विचार करना, क्योंकि हम एक साथ बहुत अच्छा सहयोग कर सकते हैं। इस क्षेत्र में, हम प्रशांत द्वीप समूह के नेताओं के मंच में, अपने विभिन्न अन्य कार्यक्रमों में, एक साथ बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। हम अच्छा समन्वय कर सकते हैं। हम अच्छा सहयोग कर सकते हैं। जब हमें कोई संयुक्त घोषणापत्र जारी करना होता है, तो हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम उन 12 बिंदुओं का पालन करें जिन्हें हमने घोषणापत्र में रेखांकित किया है, और इस क्षेत्र में आने वाले देशों के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों में, और किसी अन्य समूह के विरुद्ध उनके साथ सहयोग करने के बजाय, सहयोग करने की उम्मीद रखते हैं। क्या आप मेरा मतलब समझ रहे हैं? और प्रशांत क्षेत्र में हमारे लिए, मैं आपके दुश्मनों का भी दोस्त हो सकता हूँ, ज़रूरी नहीं कि मैं ही मेरा दोस्त होऊँ। नहीं, यह गलत है। आपका दुश्मन मेरा दोस्त है। इसलिए हम सभी को, हम सभी को दोस्त कहना चाहेंगे, और हम कहते हैं कि हम सभी के दोस्त हैं, किसी के दुश्मन नहीं हैं। अगर आप मेरे दोस्त के साथ नहीं मिलते, तो इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे आपके साथ नहीं मिलना चाहिए। इस क्षेत्र में हम सब आपस में बहुत अच्छी तरह से मिलते हैं, चाहे आपके और रिश्तेदार कोई भी हों। और यह हमारे लिए लगभग एक ही बात है। हालाँकि अब हम अलग-अलग राष्ट्र हैं, फिर भी हम एक ही हैं। हम एक जैसा सोचते हैं। हमारा स्वभाव एक जैसा है। हमें नाचना-गाना बहुत पसंद है। हमें काम से नफ़रत है। और हम बस अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। दुर्भाग्य से, हमें दुनिया के साथ आगे बढ़ना है, और उम्मीद है कि हम दुनिया को अपनी बात समझा पाएँगे। और अगर हम अलग गति से आगे बढ़ रहे हैं, तो इसकी वजह यह है कि हम प्रशांत महासागर के लोग हैं, और हम अपनी गति से तभी आगे बढ़ सकते हैं जब हमारे आसपास और हमारे बीच शांति हो।

नूतन कपूर महावर : धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। अगर आपकी अनुमति हो, तो मैं एक आखिरी प्रश्न पूछने की अनुमति दूंगी।

अज्ञात वक्ता: धन्यवाद, महामहिम। यह काफी ज्ञानवर्धक व्याख्यान था, और मुझे कहना होगा कि शांति के महासागर पर आपका दृष्टिकोण बहुत ही भविष्योन्मुखी और आशाजनक है। तो अब जबकि आपकी भारत यात्रा बहुत ही, मुझे यकीन है कि आपकी यात्रा बहुत ही उपयोगी रही होगी,

और आपने इस पर चर्चा भी की है, तो क्या आप बता सकते हैं कि दिल्ली में आपके दृष्टिकोण को कैसे स्वीकार किया गया है, और भारत में आपके वार्ताकारों से आपको क्या प्रतिक्रिया मिली है? धन्यवाद।

सितिवेनी लिगामामाडा राबुका: बहुत-बहुत धन्यवाद, महोदया। वे सभी सकारात्मक रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि इसलिए कि वे फ़िजी के मित्र हैं, भले ही मेरे कुछ मित्रों के साथ उनके मित्रतापूर्ण संबंध न हों। वे सभी बहुत सहयोगी रहे हैं। मैं पहले सिंगापुर गया था, और मैं जकार्ता गया था, और मैंने उन बड़े देशों के नेताओं से मुलाकात की। ऐसा लगता है कि सभी को शांति का विचार पसंद है। हो सकता है कि हमने इसे अपनी सोच में गहराई से नहीं उतारा हो। हो सकता है कि वे प्रशांत क्षेत्र में हमारी तरह कमज़ोर न हों, इसलिए हमें इसकी कमी बहुत खलती है। हम ऐसे लोग चाहते हैं जो संघर्ष के प्रभावों से निपटने में सक्षम हों, भले ही निकटवर्ती क्षेत्र में न हों, या दूर-दराज़ के क्षेत्रों में हो। हममें से जो अपनी अर्थव्यवस्थाओं, आकार व संघर्ष के प्रभावों और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति अपनी संवेदनशीलता के मामले में छोटे हैं, हालाँकि हम सभी अपने देश में हो रहे उत्सर्जन और उन सभी चीज़ों के लिए ज़िम्मेदार हैं, हम उनसे सहयोग की अपेक्षा करते हैं। शांतिपूर्ण ग्रामीण जीवन का मतलब यह हो सकता है कि आप शाम को सो जाएँ और इस बात की चिंता न करें कि रात में जब ज्वार आएगा तो आपका घर बह जाएगा या नहीं। ज्वार काफी ऊँचा होता है। मैं चाहता हूँ कि लोग जलवायु परिवर्तन और बढ़ते समुद्र स्तर से निपटने में सहयोग करें। मैं हर दिन अपना ईमेल देखता हूँ, और मेरे अपने कैबिनेट मंत्री ने भी चिंताएँ व्यक्त की हैं। मंत्री के गाँव में अब गाँव के सामने एक समुद्री दीवार बनाने की माँग हो रही है। दुनिया में जो कुछ हो रहा है, उसके कारण वहाँ शांति का अभाव है। इसलिए, केवल संघर्ष का अभाव ही नहीं, बल्कि मन की शांति भी प्रशांत क्षेत्र को शांति के क्षेत्र के रूप में देखने की इस अवधारणा में सबसे अहम है।

नूतन कपूर महावर : महामहिम, हमारे श्रोताओं द्वारा पूछे गए प्रश्नों के विस्तृत और व्यावहारिक उत्तर देने हेतु आपका धन्यवाद। मुझे विश्वास है कि और भी कई लोगों को आपसे सीधे बातचीत करने का अवसर पाकर खुशी होती। मैंने देखा कि छात्रों के बीच भी बहुत सारे हाथ उठे हुए थे, हालाँकि, समय की कमी को देखते हुए, हमें अभी इस सत्र को समाप्त करना चाहिए। इसी के साथ, मैं डॉ. प्रज्ञा पांडे को धन्यवाद ज्ञापन देने के लिए आमंत्रित करती हूँ।

प्रज्ञा पांडे: धन्यवाद महोदया। भारतीय वैश्विक परिषद की ओर से, मैं फिजी गणराज्य के प्रधानमंत्री, महामहिम सितिवेनी लिगामामाडा राबुका के अत्यंत ज्ञानवर्धक और विचारोत्तेजक व्याख्यान हेतु आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। हम माननीय प्रधानमंत्री के आभारी हैं कि उन्होंने शांति के महासागर पर अपना दृष्टिकोण और विज़न हमारे साथ साझा किया, जिसमें उन्होंने एकता,

स्थिरता, सतत विकास के प्रति प्रतिबद्धता और क्षेत्रीय सहयोग जैसे इसके मूल तत्वों पर प्रकाश डाला। आपकी टिप्पणियों को लेकर जो रुचि जागी है, वह हमारे श्रोताओं द्वारा पूछे गए ज्ञानवर्धक प्रश्नों और टिप्पणियों में साफ दिखाई दे रही है। हमें विश्वास है कि आपकी भारत की मौजूदा यात्रा फिजी और उसके मैत्रीपूर्ण लोगों के साथ भारत के संबंधों को और मजबूत बनाने में अहम साबित होगी, और आज का सप्रू हाउस व्याख्यान हमारी आपसी समझ और एक-दूसरे की चिंताओं व हितों के प्रति हमारी समझ को बढ़ाने का काम करेगा। मैं श्रोताओं के प्रति उनकी भागीदारी हेतु आभार व्यक्त करती हूँ। इसी के साथ यह कार्यक्रम समाप्त होता है। मैं सभी से अनुरोध करती हूँ कि कृपया तब तक अपनी जगह पर ही रहें जब तक कि गणमान्य व्यक्ति सभागार से बाहर न निकल जाएँ। आप सभी को हमारे साथ हाई टी में शामिल होने हेतु हार्दिक आमंत्रित किया जाता है, जो फ़ोयर (उपकक्ष) में आयोजित की जाएगी। आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद।